कोटद्वार, मंगलवार
10 फरवरी 2026
वर्षः 48
अंकः 257 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com

स्थापित 1979

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोनः 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

60 साल के दर्जी ने दुकान में फांसी लगाकर दी जान

देहरादून। रायपुर थाना क्षेत्र के तपोवन रोड स्थित लेन नंबर पांच में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी दर्जी की दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख–पुकार मच गई। पुलिस ने सोमवार को शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। एसओ रायपुर गिरीश नेगी ने बताया कि रविवार देर शाम सूचना मिली कि तपोवन रोड निवासी सतीश श्रीवास्तव (60) ने फांसी लगा ली है। सूचना पर मयूर विहार चौकी इंचार्ज संजय रावत पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजन उन्हें निजी वाहन से कोरोनेशन अस्पताल ले जा चुके थे। जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। प्रारंभिक पूछताछ में आत्महत्या का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।

एरीज बैंड के पास आमने–सामने टकराईं कारें

नैनीताल। नैनीताल–भवाली मार्ग पर तेज गति के चलते दो पर्यटकों की कारें आमने–सामने टकरा गईं। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सोमवार को लखनऊ निवासी प्रांजल कुमार अपनी कार से नैनीताल जा रहे थे। एरीज बैंड के पास सामने से आ रही गाजियाबाद के पर्यटक की कार गलत दिशा में आ गई और उनकी कार से टकरा गई। सूचना पर चीता कांस्टेबल अमित गहलोत मौके पर पहुंचे और दोनों वाहनों को सड़क से किनारे कराया। थानाध्यक्ष मनोज नयाल ने बताया कि गाजियाबाद के पर्यटक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए हर्जाना देने की बात कही, जिसके बाद दोनों पर्यटक अपने–अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।

महाशिवरात्रि पर्व पर वन–वे दौड़ेगा ट्रैफिक

ऋषिकेश। महाशिवरात्रि पर्व पर नीलकंठ धाम में शिव भक्तों की भीड़ बढ़ने पर ट्रैफिक वन–वे व्यवस्था के तहत दौड़ेगा। इसमें हरिद्वार से आने वाले वाहनों को गरुड़चट्टी से एंट्री दी जाएगी, जबकि वापसी करने वाले वाहन गुरुड़चट्टी के नजदीक बाइपास से होते हुए सीधे बैराज पहुंचेंगे। यहां से वाहनों को हरिद्वार की तरफ भेजा जाएगा। नीलकंठ शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर उत्तराखंड और आसपास के राज्यों से जलाभिषेक के लिए लाखों शिवक्तों की भीड़ जुटती है। 15 फरवरी को भी भोलेभक्तों का हुजूम धाम में उमड़ने की संभावना है, जिसके चलते पौड़ी पुलिस ने नीलकंठ मोटर मार्ग व आसपास ट्रैफिक को नियंत्रित रखने के लिए प्लान बनाया है। पुलिस का वन–वे ट्रैफिक प्लान भीड़ बढ़ने पर लागू होगा। स्वर्गाश्रम में तीन और नीलकंठ धाम के आसपास दो पार्किंग भी पुलिस चिन्हित कर ली हैं। इनमें ही शिव भक्तों के वाहनों का पार्क कराया जाएगा। ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए पौड़ी पुलिस पड़ोसी जिले टिहरी और देहरादून से भी समन्वय स्थापित कर रही है, जिससे कि न सिर्फ ट्रैफिक, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर रखा जा सके।

उन्नाव रेप कांड : कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका

नई दिल्ली , उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले की सुनवाई तीन महीने में पूरी करें। सेंगर ने निचली अदालत से मिली 10 साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, वहीं पीड़िता की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग की है। सेंगर के वकील ने कहा कि सेंगर 9 साल 7 महीने की सजा काट चुका है जबकि कुल सजा 10 साल की है। लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। सेंगर से जुड़े दोनों मामलों उन्नाव रेप केस और पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत की न्यायिक प्रक्रिया अलग–अलग स्तरों पर चल रही है। सीजीआई ने कहा कि इस देश में कानून का पालन होता है यहां तक कि खतरनाक आतंकवादियों और देशद्रोहियों के मामलों की भी निष्पक्ष सुनवाई होती है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यहां तक कि कसाब को भी पूरी कानूनी प्रक्रिया दी गई थी।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली पर खुशियों की सौगात

60 फीसदी तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता, एरियर का भी मिलेगा लाभ

नई दिल्ली , रंगों का त्योहार होली नजदीक है और इस बार यह त्योहार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दोहरी खुशी का कारण बन सकता है। केंद्र की मोदी सरकार होली के शुभ अवसर से ठीक पहले अपने लाखों कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है। यह खबर सीधे तौर पर कर्मचारियों की जेब और बैंक बैलेंस को प्रभावित करने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का औपचारिक ऐलान कर सकती है।

क्या 60 फीसदी के आंकड़े को छू लेगा डीए?

सरकारी गलियारों में इस वक्त सबसे अहम चर्चा डीए हाइक के नए आंकड़ों को लेकर चल रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 58 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और लेबर ब्यूरो के ताजा आंकड़ों का विश्लेषण करें तो इस बार डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की प्रबल संभावना है। यदि सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा देती है, तो 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर बेसिक सैलरी का 60 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि यह बढ़ोतरी थोड़ी और ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह पूरा गणित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिसंबर 2025 के आंकड़ों पर आधारित है।

दिल्ली में दहशत : एक साथ 9 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

नई दिल्ली , राजधानी दिल्ली में सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शहर के नौ प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकियां सुबह करीब 8.30 से 9 बजे के बीच दी गईं, जिसके चलते स्कूली बच्चों, अभिभावकों और स्टाफ में अफरा–तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वॉड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और सुरक्षा के लिहाज से सभी बच्चों व स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकालकर स्कूलों की सघन तलाशी शुरू कर दी।

एक ही समय पर आई सभी कॉल

शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि सभी स्कूलों में धमकी भरी कॉल लगभग एक ही समय पर आई थीं। इस पैटर्न को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और इसे किसी साजिश का हिस्सा मानकर जांच कर रही हैं। फिलहाल पुलिस की टीमें कॉल करने वाले की पहचान करने और कॉल की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश में जुटी हैं, ताकि आरोपी तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके।

कुंभ से संबंधित सभी तैयारियां, अक्टूबर माह तक पूरी करें : धामी

मुख्यमंत्री ने की कुम्भ मेला–2027 की तैयारियों की समीक्षा

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में कुम्भ मेला-2027, हरिद्वार की तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला हमारी संस्कृति, आस्था और करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा धार्मिक आयोजन है।

इस आयोजन को सफल बनाना हम सभी का कर्तव्य है। जो भी श्रद्धालु राज्य में आए वह अच्छा अनुभव यहां से लेकर जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ से संबंधित सभी तैयारियों को अक्टूबर माह तक पूरा किया जाए। साथ ही कुंभ की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी प्रकार के निर्माण कार्य तय समय के अंदर पूरे हों। सभी निर्माण कार्य की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। शासन स्तर पर कुंभ से संबंधित कोई भी कार्य/फाइल लंबित न रहे। किसी भी कार्य को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार की प्राथमिकता है की कुंभ मेले का भव्य दिव्य और सफल आयोजन हो। मुख्यमंत्री ने सचिव, पीडब्ल्यूडी को अगले 24 घंटे के अंदर कुंभ मेले के लिए टेक्निकल पद के अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र में बने सभी पुलों का ऑडिट किया जाए। साथ ही कुंभ क्षेत्र में स्थित सभी घाटों का सौंदर्यीकरण और आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण कार्य भी किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए हर की पैड़ी के साथ ही अन्य सभी घाटों में भी स्नान की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र में विभिन्न अखाड़ों को भूमि आवंटन तय समय पर किया जाए। इसकी मेलाधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें। साथ ही सभी अखाड़ों, मठों, संत समाज, संस्थाओं, समितियां एवं स्थानीय लोगों से समन्वय किया जाए। साथ ही उनके सुझावों के अनुरूप मेले की तैयारी हो। उन्होंने कहा मेले से संबंधित सभी विकास कार्य कागजों के साथ धरातल में भी दिखाई देने चाहिए। मुख्यमंत्री ने आवास व टेंट सिटी की तैयारी समय से पूरी करने एवं मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, एम्बुलेंस व मोबाइल चिकित्सा दल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान, विधायक श्रीमती रेनू बिष्ट, विधायक श्रीमती अनुपमा रावत, विधायक रवि बहादुर, उत्तराखण्ड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, प्रमुख सचिव एल. फैनई, आरके सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, सचिव नितेश झा, कुंभ मेलाधिकारी सोनिका सिंह एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हल्द्वानी क्रिकेट धोखाधड़ीः

विकास ढाका की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट में सुनवाई, नहीं मिली राहत

नैनीताल। हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में क्रिकेट मैच की आड़ में धोखाधड़ी के आरोपित ईवीसीएल के विकास ढाका की गिरफ्तारी को चुनौती देती याचिका में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को रिमांड सीट की प्रतिलिपि कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई को 12 फरवरी की तिथि तय की है।

सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सौरभ पाण्डे ने सात साल से कम की सजा वाली धारा में अवैध कस्टडी का आरोप लगाया है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपित विकास को पुलिस ने पूर्वाह्न 11:30 बजे पुलिस स्टेशन में बैठाया, रात नौ बजे मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और रिमांड शीट में गिरफ्तारी अगले दिन चार बजे दिखाई गई। यह भी आरोप लगाया कि किसके पुलिस दबाव में कार्य कर रही है। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गौलापार में एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग का मंगलवार से होना था। पहला मैच उत्तराखंड सोल्जर्स और दिल्ली नाइट्स के बीच खेला जाना था। प्रतियोगिता में मसूरी किंग्स, यू.पी.वारियर्स, हल्द्वानी टाइगर्स, दिल्ली नाइट्स, उत्तराखंड सोल्जर्स और वाराणसी वाइपर्स के बीच एक फरवरी से मुकाबले होने थे लेकिन देर शाम तक मैच शुरू नहीं होने पर आयोजक विकास ढाका ने बताया कि उनके बड़े पार्टनर प्रमोद सिंह की दिल्ली से हल्द्वानी निकलते वक्त हृदयगति रुकने से मृत्यु हो गई।

इस कारण शोक के चलते मैच को स्थगित किया गया है। पुलिस ने बुधवार को शिकायत प्राप्त होने के बाद विकास ढाका को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पूर्व विधायक नारायण पाल व हरियाणा के कारोबारी हेमंत शर्मा ने लाखों की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया था कि उन्होंने क्रिकेट लीग के लिए उत्तराखंड सोल्जर्स टीम खरीदी थी, 50 लाख फ्रंचाइजी फीस को दस लाख के डिस्काउंट के साथ सौदा तय किया था। फिलहाल, आरोपित विकास ढाका की जमानत टल गई है।

अजित पवार हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद बड़ा एक्शनः 400 अनियंत्रित एयरफील्ड्स की होगी जांच

नई दिल्ली , महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत चार अन्य लोगों की विमान दुर्घटना में मौत के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरकत में आ गया है। मंत्रालय ने बारामती एयरफील्ड का तत्काल निरीक्षण शुरू कर दिया है और देशभर के अनियंत्रित हवाई पट्टियों पर ऑपरेशन के लिए नए सख्त प्रोटोकॉल लागू करने की तैयारी कर रहा है। सरकार की योजना के तहत लगभग 400 अनियंत्रित एयरफील्ड्स का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान बुनियादी ढांचे की खामियों, नेविगेशन सुविधाओं की कमी और आग बुझाने जैसी इमरजेंसी सेवाओं की उपलब्धता की जांच की जाएगी। इन एयरफील्ड्स की मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और संबंधित राज्य सरकारें मिलकर संचालित करेंगी। बताया गया है कि ऐसे एयरफील्ड्स का उपयोग फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट चार्टर एयरक्राफ्ट और मूवमेंट के लिए किया जाता है। इन हवाई पट्टियों पर आमतौर पर फुल–टाइम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और नेविगेशन एड्स मौजूद नहीं होते। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, 2013 के बाद से अनियंत्रित एयरफील्ड्स पर या उनके आसपास हुई नौ विमान दुर्घटनाओं की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (ढ्डक्क) द्वारा की जा चुकी है, जिनसे सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। गौरतलब है कि 28 जनवरी को अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत एक विमान हादसे में हो गई थी।

नरवणे की पुस्तक से डर कर लोकसभा में नहीं आए मोदीः राहुल गांधी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति अभिभाषण पर नेता विपक्ष को नहीं बोलने देने पर लोकसभा में जारी गतिरोध के लिए राहुल गांधी ने सरकार को जिम्मेदार ठहराने के साथ ही स्पीकर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी र साधा निशाना

कांग्रेस की महिला सांसदों के कथित हमले के डर से पीएम धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने नहीं आने के स्पीकर के आरोपों को झूठ बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में इसलिए नहीं आए क्योंकि वे पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरावणे की पुस्तक के उठाए हमारे मुद्दे से डरे हुए हैं। महिला सांसदों से खतरे के दावों को चुनौती देते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि ऐसा था तो धमकी देने वालों पर एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तार क्यों नहीं किया। लोकसभा में सोमवार, 9 जनवरी को भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिए जाने के बाद संसद परिसर में राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि अमेरिका से जो टैरिफ समझौता हुआ है उसमें किसानों पर बहुत प्रतिकूल असर होगा।

राहुल गांधी ने कहा, 'बजट चर्चा में अमेरिकी डील में किसानों का यह मुद्दा उठेगा इसलिए सरकार बहस से डर रही है।'कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा पीएम पर सदन में हमले करने की तैयारी के आरोपों को आसन और सत्तापक्ष के दुष्प्रचार के रूप में इंगित करते हुए राहुल गांधी ने इस पर चिंता जताई और कहा कि यह सच नहीं, ऐसा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

जनरल नरवणे की किताब पर मचा बवाल

सच्चाई बहुत साफ है कि विपक्ष के सदस्यों के कारण नहीं प्रधानमंत्री जनरल नरवणे की पुस्तक से उठाए उनकी बातों से अब भी डरे हुए हैं क्योंकि वह सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। पीएम में सदन में आने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर किसी ने कहा है कि पीएम पर हमला करने वाला है तो एफआइआर कर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं।

लोकसभा में गतिरोध खत्म करने के संबंध में राहुल ने कहा कि समझौता यह है कि हमें इन बातों को सदन में कहने की अनुमति दी जाएगी और फिर बजट पर चर्चा हो और विपक्ष भी चर्चा चाहता है।

रक्षा मंत्री पर लगाए आरोप

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सदन में झूठ का दावा करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रक्षामंत्री ने कहा था कि पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, जबकि इसकी एक प्रति हमारे पास है।

नई टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं बस उसे अपना मालिक न बनने देंः पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को छात्रों से कहा कि उन्हें किसी भी नई टेक्नोलॉजी से डरने से जरूरत नहीं है, बस उसे अपना मालिक न बनने दें। यह चाहे मोबाइल हो या फिर एआई या भविष्य में आने वाली कोई टेक्नोलॉजी हो।

मोबाइल के गुलाम बन रहे बच्चेः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों में देखी जा रही मोबाइल लत का उदाहरण दिया और कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं, जो मोबाइल के इतने गुलाम हो गए हैं कि मोबाइल नहीं तो खाना नहीं खा सकते। टीवी नहीं है तो वो जी नहीं सकते है। पीएम ने इस दौरान बच्चों को अच्छे लीडर बनने का मंत्र भी दिया और कहा कि लीडर बनने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना या राजनीतिक दल बनाना नहीं है, बल्कि हम अपनी बात लोगों पर बगैर थोपे कैसे समझा पाए, यह भी होता है।

पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा

पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा के नौवें संस्करण के दूसरे एपिसोड में देश के अलग– अलग हिस्सों के छात्रों से परीक्षा व जीवन से जुड़ी चुनौतियों पर बात करे हैं। साथ ही उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। कोयंबटूर, रायपुर, गुजरात व गुवाहाटी में छात्रों के साथ बातचीत में एआई से जुड़े सवाल पर पीएम ने कहा कि एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जैसी उभरती टेक्नोलॉजी से डरने की नहीं. उनका इस्तेमाल अपने स्किल्स को बेहतर बनाने व क्षमता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों से परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करने और अच्छी नींद लेने की सलाह दी 'परीक्षाओं की अच्छी तैयारी के बाद आपको कभी तनाव महसूस नहीं होगा। अच्छी नींद आपको बाकी दिन खुश रखेगी।' पीएम मोदी से इस दौरान एक बच्चे ने पूछा कि हम बच्चों से ऐसी कौन ही क्वालिटी की उम्मीद करते हैं, जो हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे लीडर के रूप में? पीएम ने कहा कि 'देखिए लीडर से पहले निडर बनिए। जो काम है, मन में तय करिए। कोई करे या न करे, उसे करिए। लीडरशिप में एक क्वालिटी होना बहुत जरूरी है कि आप दस लोगों को अपनी बात समझाए, थोपे नहीं।' कैरियर चुनने से जुड़े सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, 'लगातार बदलती ख्वाहिशों से परिवार कन्फ्यूज हो जाते हैं लेकिन सफल लोगों से इंस्पायर होना नैचुरल है।

पटना सिविल कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी

पटना ,पटना सिविल कोर्ट को आज एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर में अफरा–तफरी का माहौल बन गया। सिविल कोर्ट और जिला बार एसोसिएशन को एक ईमेल के जरिए यह धमकी भरा पत्र भेजा गया है।

ईमेल में दावा किया गया है कि कोर्ट परिसर में बम प्लांट किए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया है। धमकी भरे ईमेल में बेहद सनसनीखेज और खतरनाक बातें लिखी गई हैं। मेल भेजने वाले ने लिखा है कि जजों के चैंबर और वॉशरूम में 4 आरडीएक्स रखे गए हैं, जिन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए ब्लास्ट किया जाएगा।

इस सूचना के मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। आनन–फानन में सभी जज और वकील अपने चैंबर छोड़कर बाहर सुरक्षित स्थानों पर निकल आए।

कैंचीधाम बाईपास 15 जून तक हर हाल में शुरू करेंः सतपाल

नैनीताल। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कैंचीधाम बाईपास मार्ग को 15 जून तक हर हाल में यातायात के लिए खोल दिया जाए। यदि 75 मीटर स्पान के पुल निर्माण में विलंब होता है तो अस्थायी वेली ब्रिज लगाकर मार्ग चालू किया जाए। सोमवार को विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने लोक निर्माण विभाग की कुल पांच योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें 945.99 लाख की चार योजनाओं का शिलान्यास तथा 312.13 लाख की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। कुल योजनाओं की लागत 1258.12 लाख है। समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि सरकार सड़कों की कनेक्टिविटी को लेकर गंभीर है। अब तक 14,027 गांवों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने बढ़ते यातायात को देखते हुए प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और गुणवत्ता युक्त निर्माण के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग को क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत, भीमताल–नौकुचियाताल नहर से अतिक्रमण हटाने और भू–कटाव रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। पंचायतीराज विभाग को कूड़ा निस्तारण की बेहतर व्यवस्था और पर्यटन विभाग को होम–स्टे में स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

आयोध्या में धमाके की साजिश रचने वाले आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या

कश्मीरी कैदी ने किया हमला

फरीदाबाद , हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले की जेल में बंद 20 वर्षीय आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, यह हमला जेल में ही हुआ, जहां एक अन्य कैदी ने नुकीली चीज से उसके सिर पर हमला किया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि हमलावर का नाम अरुण चौधरी है, जो कश्मीरी युवक है। रविवार रात को उसने अब्दुल रहमान पर हमला किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि अब्दुल रहमान 2 मार्च 2025 को पाली गांव के पास से पकड़ा गया था। उस समय उसके पास दो हैंड ग्रेनेड थे और वह अयोध्या में धमाका करने की साजिश रच रहा था। उसे उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का रहने वाला बताया गया। अब्दुल रहमान के पास कुछ वीडियो भी मिले थे, जिनमें राम मंदिर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी थी। इसे देखते हुए एसटीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। उसके पास पाए गए दो हैंड ग्रेनेड को तुरंत डिफ्यूज कर दिया गया।वहीं, जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान पर हमला करने और उसकी जान लेने वाला आरोपी पहले जम्मू–कश्मीर की जेल में बंद था, जिसे बाद में फरीदाबाद जेल में शिफ्ट किया गया था। वह भी हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद था। जेल में अब्दुल रहमान की हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब जेल में किसी कैदी पर हमला हुआ हो, लेकिन सुरक्षा के इतने सख्त इंतजाम के बावजूद ऐसा होना चिंताजनक है।

मंदिर की छत गिरी, प्रसाद लेने गईं 3 बच्चियों की मौत, पति–पत्नी समेत 5 घायल

मुरैना ,मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। कैलारस क्षेत्र के एहरौली गांव स्थित चामड़ माता मंदिर में अचानक छत भरभराकर गिर गई।

हादसे के वक्त मंदिर में प्रसाद लेने गईं 3 मासूम बच्चियों की मलबे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दंपति और तीन अन्य बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मंदिर में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के दौरान अचानक छत टूटकर नीचे गिर गई, जिससे अफरा–तफरी मच गई। मलबे में दबने से तीन बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत–बचाव कार्य शुरू किया।

आरएसएस के चलते ही भाजपा के अच्छे दिन आए, राम मंदिर का भी मिला फायदाः मोहन भागवत

नई दिल्ली ,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भाजपा और संघ के रिश्तों को लेकर एक बार फिर स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा को मिले 'अच्छे दिनझ् आरएसएस की तपस्या और प्रतिबद्धता का ही परिणाम हैं। भागवत का यह बयान 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के उस कथन के बाद अहम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा आरएसएस के बिना भी चुनाव जीत सकती है। उस बयान को लेकर संघ कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा गया था। सरसंघचालक ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के लिए आरएसएस ने दशकों तक निरंतर प्रयास किए और जिसने इस आंदोलन का साथ दिया, उसे राजनीतिक रूप से भी लाभ मिला। उन्होंने संकेतों में यह भी स्पष्ट कर दिया कि संघ के नेतृत्व में चले आंदोलनों का फायदा भाजपा को चुनावी राजनीति में मिला है।

भागवत ने यह भी रेखांकित किया कि भाजपा का वैचारिक आधार आज भी आरएसएस ही है और संघ उसका मातृ संगठन बना हुआ है। माना जा रहा है कि यह बयान संघ कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के साथ–साथ भाजपा नेतृत्व के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि संगठन का विस्तार चाहे जितना हो जाए, उसकी जड़ें अब भी संघ की विचारधारा में ही हैं। उन्होंने आरएसएस और भाजपा के संबंधों पर उठते सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि संघ भाजपा को स्वयंसेवक देता है, लेकिन पार्टी के निर्णयों में संघ का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक कार्यरत हैं, लेकिन वह संघ की पार्टी नहीं है।

सम्पादकीय

स्वर्ण समाज की एकजुटता

देश में जातियों को लेकर जिस प्रकार का विद्वेष पिछले कुछ वर्षों में पनपता हुआ नजर आया है उसके पीछे केंद्र सरकार की वह नीतियां सबसे अधिक जिम्मेदार है जो समाज को बांटने का काम कर रही है। यह तो तय हो गया है कि अब आने वाला समय देश जातिगत एवं आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक बड़ी करवट लेने वाला है। जिस प्रकार से जाति व्यवस्था को लेकर बेशुमार अनर्गल झूठे मुकदमे स्वर्ण लोगों किए जा रहे हैं उसने इस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक आरक्षण को लेकर स्वर्ण समाज द्वारा यूं तो खुलकर आवाज नहीं उठाई जा रही थी लेकिन पिछले दिनों यूजीसी कानून लाने के बाद तो मानो दबे हुए स्वर अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं। स्वर्ण समाज के विरोध के कारण यूजीसी एक्ट फिलहाल स्थगित करना पड़ा लेकिन जिस कारण यह स्थगित हुआ वह यह बताने के लिए काफी है की एक वर्ग को हर मोर्चे और स्तर पर दबाने की सरकार की कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी। वह भी तब जब सरकार की मंशा दलित की आड़ में वोट बैंक पर हो। आरक्षण के दंश ने पूरे देश की व्यवस्था पर विष फैलाने का काम किया है, लेकिन कहते हैं जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो फिर बचने के प्रयास करने ही पड़ते हैं। पूरे देश के अंदर स्वर्ण समाज का एकजुट होना सरकार के लिए खतरे की घंटी भी बनता हुआ नजर आ रहा है लेकिन सरकार शायद अभी भी यह समझने को तैयार नहीं है कि जिस वर्ग को वह अब तक अपना निर्विवाद वोट बैंक समझती आ रही थी वह आने वाले दिनों में करवट भी ले सकता है। केंद्र सरकार ने यूजीसी एक्ट लाकर दलित वर्ग के वोट बैंक पर सेंध मार कर भले ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी एवं अन्य ऐसे दल जो इस वर्ग को अपना वोट बैंक मानता है, उन पर निश्चित तौर पर घात लगाई है लेकिन यहां केंद्र सरकार ने स्वर्णों का वह विश्वास खो दिया है जिसने पिछले दो लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी एक बड़ा प्रतिशत वोटो का बीजेपी को दिया है। एक लंबे अरसे के बाद स्वर्ण समाज के लोग सरकार की जातिगत आरक्षण व्यवस्था के विरोध में खुलकर मैदान में देखने को मिल रहे हैं। भाजपा को शायद यह मुगालता हो चुका है कि वह चाहे दलितों को खुश करने के लिए स्वर्ण समाज का चाहे जितना भी दमन कर ले वोट बैंक स्थिर रहेगा। हालात अब बदलने लगे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के कैंप में इसकी चिंता भी नजर आने लगी है। विडंबना यह है की स्वर्ण समाज सरकार में शामिल अपने ही स्वर्ण नेताओं के व्यवहार एवं यूजीसी के मुद्दे पर मौन से काफी दुखी है और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारत में जातिगत आरक्षण अब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है जिसने इस समाज के होनहार नोनीहालों के भविष्य के रास्ते लगभग बंद कर दिए हैं तो वहीं झूठे मुकदमों को भी झेलना पड़ रहा है। अब सरकार को इस दिशा में बड़ा कदम उठाना होगा अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब समाज के अंदर बड़ा विघटन एवं हिंदुओं के बीच ही एक बड़ा सामाजिक द्वंद्व देखने को मिलेगा

भारत—यूरोपीय संघ व्यापार समझौता

श्री राजेश अग्रवाल

भारत का यूरोप के साथ 250 ईसा पूर्व से एक समृद्ध व्यापारिक संबंध रहा है, जो सिल्क रोड से भी पहले की अवधि है। अगले 2000 वर्षों के अधिकांश हिस्से के दौरान, भारतीय मसलिन, कपास, हस्तशिल्प, मसाले, पन्ना और रत्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे पसंदीदा वस्तुओं में शुमार होते थे, जिनमें से अधिकांश यूरोप तक पहुँचती थीं। इन शानदार वस्तुओं के भुगतान के तौर पर भारत को सोना और चांदी मिलते थे। अपने सुनहरे दिनों में, भारत—यूरोप व्यापार ने मात्रा और पैमाने की दृष्टि से अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की।

एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से इस संबंध को सुदृढ़ करने के प्रयास 2007 में शुरू हुए थे। गंभीर मतभेदों के कारण 2013 में बातचीत को रोकना पड़ा, क्योंकि कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के विचार अलग थे। 2022 में बातचीत फिर से शुरू हुई और चुनौतियों की जटिलता के बावजूद इसे केवल दोनों राजनेताओं की मजबूत प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण अंतिम रूप दिया जा सका। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यापार समझौते को दोनों पक्षों ने बातचीत के माध्यम से पूरा किया है, वह अस्थिर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नियम—आधारित व्यापार संबंध की पुष्टि करता है। यह समझौता ऐतिहासिक है सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें शामिल विषय और क्षेत्र व्यापक हैं; समझौता ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि दोनों पक्षों को ऐसे मुद्दों पर साझा रुख अपनाना पड़ा, जो कठिन और जटिल थे।

सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौताः भारत—ईयू मुक्त व्यापार समझौता शायद हाल के समय में किया गया सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। यह दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक का निर्माण कर सकता है, जिसमें लगभग 2 अरब लोग और 28 देश शामिल होंगे और जो वैश्विक जीडीपी का 25 प्रतिशत है। इसके अलावा, यह समझौता मुद्दों और चिंताओं के समाधान के सन्दर्भ में आधुनिक और नवीन है। इस समझौते में व्यापार संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए अद्यतन और मूल विषयों के साथ—साथ प्रक्रिया—संबंधी प्रावधान भी हैं। यह समझौता वस्तु और सेवा; दोनों के लिए बाजार पहुंच और नियामक बाधाओं के समाधान के लिए एक नया मॉडल स्थापित करता है, जो पारंपरिक विषयों को नवाचार—तत्वों के साथ सुदृढ़ करता है। उदाहरण के लिए, उत्पत्ति के नियमों का अध्याय सुनिश्चित करता है कि केवल वही उत्पाद जिनका पर्याप्त प्रसंस्करण या उत्पादन साझेदार देशों में हुआ है, उन्हें मूल देश का प्रमाण दिया जाएगा; इसे विस्तृत और जटिल उत्पाद—विशिष्ट नियमों के माध्यम से हासिल किया गया है, जो मौजूदा और नयी आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुरूप हैं। इसके अलावा, यह समझौता बौद्धिक संपदा संरक्षण को पुनर्स्थापित करता है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व सूचना प्रवाह को बढ़ावा देने पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करता है।

वस्तु और सेवाओं के लिए बाजार खोलनाः समझौते का मुख्य ध्यान दोनों पक्षों के विशाल और व्यापक बाजारों को एक—दूसरे के लिए खोलना है। यह समझौता भारत के निर्यात व्यापार मूल्य के 99 प्रतिशत से अधिक के लिए बाजार पहुँच प्रदान करता है, जिसमें कम से कम 90 प्रतिशत भारतीय निर्यात को समझौते के लागू होने पर तुरंत निःशुल्कच प्रवेश की सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से, श्रम—सघन वस्तुएँ जैसे वस्त्र और परिधान, चमड़ा, रत्न और आभूषण, लकड़ी और लकड़ी की शिल्पकला और समुद्री उत्पादों को जल्दी लाभ मिलेगा। यह रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि—प्रसंस्करण उद्योग और खनिज जैसे उद्योगों को भी जीवंत ईयू सामान्य बाजार में अपने निर्यात को विविधता देने में सक्षम करेगा। हालांकि, भारत ने ईयू वाहन के लिए बाजार पहुँच की अनुमति दी है, लेकिन इसे चरणबद्ध और सन्तुलित तरीके से टैरिफ कोटा के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया है। इसी तरह, यूरोपीय संघ की शराब पर भारत की छूट घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के साथ—साथ उच्च मूल्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है।

सेवाओं के व्यापार के लिए भारत—ईयू व्यापार संबंध में महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं। इस समझौते के तहत भारत ने 144 सेवा क्षेत्रों में ईयू की प्रतिबद्धताएँ प्राप्त की हैं, जो कि अभूतपूर्व है। इसके अलावा, गतिशीलता पर अध्याय यह सुनिश्चित करता है कि पेशेवरों और संविदा सेवा प्रदाताओं का अस्थायी प्रवेश और निवास सरल और भरोसेमंद होगा, जिसका अर्थ है कि भारत के प्रतिभाशाली सेवा पेशेवर ईयू बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। वित्तीय सेवाओं पर संलग्नक भारत और ईयू के बीच इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों पर अधिक सहभागिता का प्रावधान करता है, जिसमें भारत की डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसे यूपीआई में तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग शामिल है। यह समझौता आयुष और पारंपरिक चिकित्सा कर्मियों को भी अधिक निश्चितता के साथ ईयू में अपनी सेवाएँ प्रदान करने की संभावना पेश करता है।

मुक्त और न्यायसंगत व्यापार को बढ़ावा देनाः मुक्त व्यापार समझौता दो बड़े बाजारों के बीच मुक्त, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। व्यापार और सतत विकास अध्याय सतत विकास संबंधी चिंताओं के संदर्भ में सहयोग का एक नया मॉडल प्रस्तुत करता है। यह अध्याय दोनों पक्षों के श्रम या पर्यावरण मानकों में तालमेल बिठाये बिना दोनों पक्षों के व्यापार संबंध में सतत विकास के उद्देश्य को समग्र रूप से एकीकृत करता है। इस सहभागिता का मुख्य उद्देश्य नीति संवाद, तकनीकी सहायता और वित्तीय उपकरणों और संसाधनों को जुटाने पर है। दोनों पक्षों ने त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र, गैर—उल्लंघन शिकायतें और स्वतंत्र परिशिष्ट जैसी व्यवस्थाओं पर भी बातचीत की है, जो कुछ नीति उपायों या उत्पाद—विशिष्ट उपायों के संबंध में उनकी विशिष्ट चिंताओं का समाधान कर सकते हैं।

असल चुनौती यह थी कि कुछ महत्वपूर्ण हितधारकों, जैसे कि डेयरी और कृषि क्षेत्र, की चिंताओं और संवेदनशीलताओं की अनदेखी किए बिना बाजार खोलने के उच्च महत्वाकांक्षा को हासिल किया जा सके। छोटे और सीमांत किसानों और कुछ उद्योग क्षेत्रों की आय और जीवनयापन की चिंताएं हमारे मन में सबसे पहले थीं। ईमानदारी से कहें तो, इस मामले में यूरोपीय संघ ने आवश्यक लचीलापन भी दिखाया।

भारत की एफटीए रणनीति का पूरकः आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के युग में, भारत—ईयू मुक्त व्यापार समझौता; भारत—यूके एफटीए, ईएफटीए और अन्य व्यापक व्यापार समझौतों से हुए लाभ में पूरक की भूमिका निभाएगा। 2021 से, भारत ने 9 व्यापक व्यापार समझौते किए हैं और अगले कुछ महीनों में कई प्रमुख आर्थिक साझेदारी समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता कर रहा है। भारत—ईयू व्यापार समझौते का निष्कर्ष भारत की नई आर्थिक और व्यापारिक पहलों को तेज करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।भारत—ईयू मुक्त व्यापार समझौता विस्तारित बाजार पहुंच, नजदीकी आर्थिक एकीकरण और विशेष रूप से अनिश्चित और अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में रणनीतिक स्वायत्तता और सुदृढ़ता प्राप्त करने में एक बड़ा कदम है। जैसा कि आर्थिक इतिहासकार उल्लेख करते हैं, आर्थिक समृद्धि सबसे अच्छे तरीके से तब प्राप्त की जा सकती है जब राष्ट्र न्यायपूर्ण, नियम—आधारित और पूर्व अनुमान योग्य कानूनी रूपरेखा और संस्थानों के आधार पर व्यापार करते हैं। भारत—ईयू मुक्त व्यापार समझौता समय पर खरे उतरे इस सिद्धांत को बनाए रखने का प्रयास करता है।

नई दवाओं के विकास

भारत सरकार ने नई दवाओं के विकास के लिए हरी झंडी देने के नियम आसान बनाए हैं। इसके लिए नई औषधि एवं क्लीनिकल ट्रायल के 2019 में बने नियमों में बदलाव किया गया है। मकसद नई दवाओं के परीक्षण में लगने वाले समय को घटाना और संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। पहले ऐसे कार्यों के लिए केंद्रीय औषधि प्रमाणन नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य था। अब कंपनियां कुछ श्रेणियों की दवाओं को छोड़कर बाकी सभी मामलों में सीडीएससीओ को महज ऑनलाइन सूचना देकर परीक्षण शुरू कर सकेंगी।

अनुसंधान एवं परीक्षण की गतिविधियों को नौकरशाही सुस्ती से मुक्त करना सही दिशा में कदम है। लेकिन इसे सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि दवा कंपनियां नियमों में दी जा रही रियायत का बेज़ा फायदा ना उठाएं।

भारत सरकार ने नई दवाओं के विकास के लिए हरी झंडी देने के नियम आसान बनाए हैं। इसके लिए नई औषधि एवं क्लीनिकल ट्रायल के 2019 में बने नियमों में बदलाव किया गया है। मकसद नई दवाओं के परीक्षण में लगने वाले समय को घटाना और संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। पहले ऐसे कार्यों के लिए केंद्रीय औषधि प्रमाणन नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य था। अब कंपनियां कुछ श्रेणियों की दवाओं को छोड़कर बाकी सभी मामलों में सीडीएससीओ को महज ऑनलाइन सूचना देकर परीक्षण शुरू कर सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस बदलाव से कम—से—कम 90 दिन की बचत होगी। दवा कंपनियां लंबे समय से ऐसे बदलाव की मांग कर रही थीं। विनियमन प्रक्रिया की धीमी गति को वे अपने लिए बड़ी रुकावट मानती रही हैं। अतः अनुसंधान एवं परीक्षण की गतिविधियों को नौकरशाही सुस्ती से मुक्त करना सही दिशा में कदम है। लेकिन इसे सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि कंपनियां नियमों में ढीलेपन का बेज़ा फायदा ना उठाएं। हालांकि भारतीय दवा उद्योग की दुनिया में ऊंची साख है, लेकिन हाल के वर्षों में कंपनियों द्वारा विनियमन प्रक्रिया में ढिलाई का लाभ उठाने के कई मामलों सामने आए हैं। कफ सिरप जैसी दवाओं से मिलावट की घटनाओं से भारतीय औषधि उद्योग पर कलंक लगा है। आम धारणा है कि भारत में निगरानी की व्यवस्था पश्चिमी देशों में मौजूद विनियम से कमजोर है।

इसी कारण भारत में बनी जेनरिक दवाओं को ब्रांडेड दवाओं से अक्सर कमतर समझा जाता है। इसके बावजूद भारत में बनी दवाओं और वैक्सीन का दुनिया में बहुत बड़ा बाजार है, तो उसकी वजह इनका किफायती होना है। दवा उत्पादन के लिहाज से भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के लिहाज से 14वें स्थान पर आता है। देश में तीन हजार से ज्यादा दवा कंपनियां और साढ़े दस हजार फैक्टरियां हैं। लगभग 60 जेनरिक ब्रांड यहां उत्पादित होते हैं। इस कारोबार ने दशकों के दरम्यान इतना विशाल आकार ग्रहण किया है, तो उसमें विश्वसनीयता एक निर्णायक पहलू रही है। नए बदलावों के साथ इस पर कोई समझौता नहीं हो, इसे अवश्य सुनिश्चित करना होगा।

वर्तमान एंव भावी पीढ़ियों पर बोझ

केंद्रीय आमदनी में कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा 18 फीसदी ही रह गया है, जबकि आम लोगों का कर योगदान 46 फीसदी पहुंच गया है। यह प्रतिगामी सूरत है। बजट से साफ है कि इसमें सुधार का कोई प्रयास नहीं किया गया है। केंद्रीय बजट में 2026—27 में 53,47,315 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसका 24 फीसदी हिस्सा कर्ज लेकर जुटाया जाएगा। बाकी रकम टैक्स और गैर कर स्रोतों से आएगी। सरकार जो खर्च करेगी, उसका 20 प्रतिशत हिस्सा पहले से मौजूद कर्ज का ब्याज चुकाने में जाएगा। 22 प्रतिशत हिस्सा उगाहे गए कर में राज्यों का हिस्सा देने, 11 प्रतिशत हिस्सा रक्षा, और दो प्रतिशत केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन पर खर्च हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र के अपने प्रशासनिक खर्चे हैं। उन सबके बाद पूंजीगत निवेश के लिए लगभग 17 करोड़ (सवा 12 लाख करोड़ सीधे पूंजीगत निवेश और सवा पांच करोड़ पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान) के लिए बचेंगे। अगले वित्त वर्ष में केंद्र लगभग 17 लाख करोड़ रुपये के नए कर्ज लेगा। मगर इससे भी प्रस्तावित खर्च पूरा नहीं होगा। कुल मिलाकर 4.3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा रह जाएगा। ये रविवार को पेश हुए आम बजट का सीधा गणित है। जब सरकार का लगभग एक चौथाई बजट कर चुकाने पर खर्च होने लगा है, तो समझा जा सकता है कि देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है। पिछले साल केंद्र ने 14 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया। इस वर्ष उससे तीन लाख करोड़ रुपये अधिक लेने का इरादा उसने रखा है, तो उसकी वजह यही है कि अब ऋण चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ रहा है। चालू वित्त वर्ष में केंद्र ने आय कर और जीएसटी दरों में छूट देकर अपने लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों करों से होने वाले आय को घटाया। नतीजतन, उसे और अधिक ऋण लेना पड़ेगा। सरकार चाहती, तो कॉरपोरेट टैक्स में 2019 में दी गई छूट वापस लेकर तथा धनी लोगों पर नए कर लगाकर राजकोषीय सेहत सुधार सकती थी। अब उसकी कुल आमदनी में कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा 18 फीसदी ही रह गया है, जबकि (व्यक्तिगत आयकर 21 प्रतिशत, जीएसटी 15 प्रतिशत, उत्पाद एवं कस्टम 10 प्रतिशत मिला दें, तो) आम लोगों का कर योगदान 46 फीसदी तक पहुंच गया है। यह प्रतिगामी सूरत है।

धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले ही बनाया बड़ा रिकॉर्ड

आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बवाल काटा और कमाई के मामले में एक नया इतिहास रच दिया है। रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और अब ओटीटी पर छाई है। ओटीटी पर भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब रणवीर सिंह धुरंधर 2 से नया बवाल काटने को तैयार हैं। पिछले ही दिनों मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी किया था और अब रिलीज से पहले ही धुरंधर 2 या धुरंधरः द रिवेंज ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। जी हैं, फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने हाल ही में एक बड़ी डील लॉक की है।

धुरंधरः द रिवेंज 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इससे पहले ही इस फिल्म ने 245 करोड़ की कमाई कर ली है। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, आदित्य धर की फिल्म के सीक्वल यानी धुरंधर 2 ने अपने नॉन—थिएट्रिकल राइट्स से 245 करोड़ कमा लिए हैं और इसी के साथ ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी डील्स में से एक बन गई है। बताया जा रहा है कि जियो हॉटस्टार ने धुरंधर 2 के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स 150 करोड़ में खरीद लिए हैं। वहीं फिल्म के सैटेलाइट राइट्स (सभी भाषाओं में) स्टार नेटवर्क ने खरीदे हैं और वो भी 50 करोड़ में। वहीं फिल्म के म्यूजिकल राइट्स की बात करें तो आदित्य धर ने ये डील टी—सीरीज के साथ पक्की की है और ये डील 45 करोड़ में डन हुई है। यानी, फिल्म ने रिलीज से पहले ही 245 करोड़ की कमाई कर ली है।

तीन खिलाड़ियों की बड़ी उपलब्धि के साथ जिम्बाब्वे ने बजाया जीत का बिगुल

नई दिल्ली। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत जिम्बाब्वे ने सोमवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। कोलंबो के एसएससी मैदान पर जिम्बाब्वे ने ओमान को 39 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से मात दी। ग्रुप बी के टूर्नामेंट के आठवें मुकाबले में ओमान ने पहले बल्लेबाजी के आमंत्रण को स्वीकार किया और उसकी पूरी टीम 19.5 ओवर में 103 रन पर ऑलआउट हुई। जवाब में जिम्बाब्वे ने 13.3 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 4 ओवर में एक मेडन सहित 16 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

बेनेट की उम्दा पारी

104 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे को ओपनर्स ब्रायन बेनेट (48*) और तदीवनाशे मरुमानी (21) ने 30 रन की साझेदारी करके सधी हुई शुरुआत दिलाई। महमूद ने तीन गेंदों के अंतराल में मरुमानी और डियोन मायर्स के विकेट लेकर जिम्बाब्वे पर दबाव बनाया। ब्रायन बेनेट ने अनुभवी ब्रेंडन टेलर (31 रिटायर्ड हर्ट) के साथ तीसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी करके जिम्बाब्वे की जीत सुनिश्चित कर दी। सिकंदर रजा (5*) ने विजयी चौका लगाया। बेनेट ने 36 गेंदों में 7 चौके की मदद से नाबाद 48 रन बनाए। टेलर ने 30 गेंदों में तीन चौके की मदद से 30 रन बनाए। ओमान की तरफ से दोनों विकेट सुफ्यान महमूद ने लिए।

जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का कहर

इससे पहले ओमान की शुरुआत बेहद खराब रही। 27 रन पर उसकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। ओमान को पहला झटका मुजरबानी ने दिया, जिन्होंने ओमान के कप्तान और ओपनर जतिंदर सिंह को क्लीन बोल्ड किया। फिर हम्माद मिर्जा और करण सोनावले खाता भी नहीं खोल सके। ओमान की तरफ से केवल तीन बल्लेबाज दहाई संख्या में रन बना सके। सुफ्यान महमूद (25), विनायक शुक्ला (28) और नदीम खान (20) ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का कुछ हद तक सामना कर सके। जिम्बाब्वे की तरफ से मुजरबानी के अलावा रिचर्ड एनगरावा और ब्रेड इवांस ने तीन—तीन विकेट झटके। सिकंदर रजा को एक सफलता मिली।

ओ रोमियो का नया गाना पान की दुकान हुआ रिलीज

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज होने से पहले काफी ज्यादा विवादों का सामना कर रही है. इस बीच, फिल्म का नया गाना पान की दुकान रिलीज कर दिया गया है. फैंस को शाहिद का ये गाना काफी पसंद आ रहा है. अभिनेता शाहिद कपूर ने मुंबई में एक इवेंट के दौरान नया गाना पान की दुकान रिलीज किया है. सॉन्ग पान की दुकान एक हाई—एनर्जी वाला डांस नंबर है, जिसमें शाहिद कपूर का स्वैग और डांस स्टेप्स कमाल के हैं. गाने में उनके डांस मूव्स दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. ये गाना इतना जबरदस्त है कि इसे सुनकर हर कोई झूमने को मजबूर हो जाए. वहीं, गाने में दिशा की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिए हैं. गाने में उनकी ग्रेसफुल और ग्लैमरस परफॉर्मेंस फैंस को और भी ज्यादा भा रही है. गाने को सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज ने मिलकर गाया है, जबकि इसके लिरिक्स गुलजार साहब ने लिखे हैं और विशाल भारद्वाज ने इसका संगीत तैयार किया है. विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोडक्शन नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की तरफ से है.

ओटीटी पर रिलीज हुई कार्तिक—अनन्या की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी पिछले साल सिनेमाघरों में क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म से यूं तो बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाने की उम्मीद थी लेकिन धुरंधर के तूफान के आगे ये टिक नहीं पाई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. हालांकि फैंस कार्तिक की इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे तो ये रोमांटिक ड्रामा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है. चलिए यहां जानते हैं तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को ओटीटी पर कहां देख सकते हैं ? तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी फाइनली ओटीटी पर आ गई है. यह फिल्म क्रिसमस 2025 वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. बहुत से लोग इसे घर पर देखने का इंतज़ार कर रहे थे, और अब यह आखिरकार आ गई है. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है,

भारत के खिलाफ पाकिस्तान—बांग्लादेश की बड़ी साजिश

नई दिल्ली। भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहा है। आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मुलाकात की और इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया। हालांकि, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही अलग सुर में राग अलाप रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने आईसीसी से मांग की है, जिसमें उन्होंने वर्तमान हाइब्रिड मॉडल को 2031 तक बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद को देखते हुए हाइब्रिड मॉडल बनाया था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान 2027 तक एक—दूसरे के देश अपना मुकाबला नहीं खेलेंगे। अब इसे उन्होंने 2031 तक बढ़ाने की मांग की है। पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ अमीनुल इस्लाम के साथ आईसीसी उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा ने मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने ये मांग रखी कि हाइब्रिड मॉडल को 2031 तक बढ़ाया जाए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस मांग से भारत को बड़ा झटका लगा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 भारत और बांग्लादेश की मेजबानी में खेला जाना है। इस मांग के तहत पाकिस्तान ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वो अपने सभी मुकाबले बांग्लादेश में ही खेलें। हालांकि, अंतिम फैसला आईसीसी पर निर्भर करेगा कि वे इस मांग को स्वीकार करते हैं या नहीं। हालांकि, अगर पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश में शिफ्ट करने पड़े, तो इससे भारत को मेजबानी में कम मुकाबले मिलेंगे, जिससे कमाई पर भी असर पड़ेगा।

बैठक के बाद नहीं हुआ कोई एलान

लाहौर में बैठक के बाद न तो पीसीबी और न ही आईसीसी की ओर से कोई भी एलान किया गया। ये बैठक 4 घंटे तक चली थी और अब पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी अपनी सरकार से बात करने के बाद आईसीसी को अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे।

एक नजर

14 साल बाद थमाया बिजली बिल, आयोग ने लगाई विभाग को फटकार

पौड़ी। 14 वर्षों बाद उपभोक्ता पर बिजली बिल के भुगतान का दबाव बनाना विद्युत वितरण खंड पौड़ी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (डीसीडीआरसी) ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विभाग को वसूली गई 3,447 रुपये लौटाने के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार और वाद व्यय के लिए 5 हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश डीसीडीआरसी पौड़ी के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता की अदालत ने सुनाया। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार भट्ट निवासी ग्राम देवल विकासखंड कोट ने आयोग को बताया कि ग्राम कोट और देवल स्थित उनके पैतृक भवनों में लिए गए दोनों बिजली कनेक्शन का पूरा भुगतान करने के बाद उन्हें विधिवत कटवा दिया गया था। इसके बावजूद विद्युत वितरण खंड पौड़ी ने न तो जमानत धनराशि लौटाई और न ही किसी प्रकार के बकाया की सूचना दी।शिकायत के अनुसार विभाग ने वर्ष 2005 से 2019 तक का बकाया बताते हुए बिना पूर्व सूचना के 28 जून 2019 को तहसीलदार पौड़ी के माध्यम से आरसी जारी कर दी। 21 जून 2019 को भेजे गए नोटिस में 3,133 रुपये की राशि 10 प्रतिशत संयोजन शुल्क सहित जमा न करने पर गिरफ्तारी व संपत्ति कुर्की की चेतावनी दी गई। दबाव में आकर शिकायतकर्ता को ब्याज सहित 3,447 रुपये जमा करने पड़े। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन तभी काटा जाता है जब सभी देयकों का भुगतान हो चुका हो। विभाग कनेक्शन कटने के समय किसी भी वैध बकाया को प्रमाणित करने में असफल रहा। कहा कि 14 वर्षों बाद बिना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य और वैध मांगपत्र के आरसी जारी करना मनमाना रवैया है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। साथ ही आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी का संतोषजनक उत्तर न देना विभागीय अपारदर्शिता को दर्शाता है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 के तहत सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। आदेश के अनुसार विद्युत विभाग को 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को कुल 18,447 रुपये का भुगतान करना होगा। समय पर भुगतान न होने की स्थिति में आयोग ने विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

पेयजल लाइन तोड़कर आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगाया

नई टिहरी। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दरबार में दूर–दराज क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं रखते हुए निस्तारण करने की मांग की। डीएम नितिका खंडेलवाल ने कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को अग्रसारित कर समस्याएं शीघ्र हल करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में कलेक्ट्रेट पहुंची सौड़ बमुंड की सुरमा देवी ने मसूरी फल पट्टी के उपला सौड़ में पति के नाम स्वीकृत पट्टे के पुनर्जीवित करने की मांग की। हटवाल गांव के बुद्धि ने पुनर्वास नीति के तहत आवंटित प्लॉट से फलदार वृक्ष कटवाने की मांग की। दोगी पट्टी में लोयल गांव के रमेश सिंह पुंडीर ने कारगिल शहीद जगत सिंह मोटर मार्ग पर कुंडिया नामे तोक में स्थित प्राथमिक स्कूल की क्षतिग्रस्त दीवार बनाने की मांग उठाई। गजा पाली के ग्रामीणों ने पाली के 10 परिवारों की पेयजल लाइन जानबूझ कर क्षतिग्रस्त कर पेयजल आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगाया।

जाखणीधार गेंवली निवासी शांति प्रसाद सेमवाल और राजेश्वर प्रसाद सेमवाल ने सड़क टूटने से क्षतिग्रस्त आवासीय भवन की मरम्मत की मांग की। प्रतापनगर के चाका मुखमाल गांव से आए ग्रामीणों ने गांव को सड़क से जोड़ने की मांग की। जाखणीधार पालकोट के सुंदर सिंह को कंबल और स्वाटर दी गई।

इस तरह जनता दरबार में 40 शिकायतें दर्ज कराई गईं। इस दौरान डीएम ने सभी एसडीएम को चारधाम यात्रा मार्ग से अतिक्रमण हटाकर व्यवस्थाएं जुटाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम अवधेश कुमार सिंह, सीएमओ डॉ. श्याम विजय और एसडीएम स्नेहिल कुंवर आदि मौजूद थे।

सीएस बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिवगणों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर दिशानिर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां ले ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने सभी कार्यों को लेकर वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर, उसके अनुसार अपनी सभी गतिविधियों को संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कुम्भ मेला – 2027 से सम्बन्धित कार्यों को भी प्राथमिकता पर लेते हुए सभी प्रकार की स्वीकृतियां और प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा के मापदण्डों का प्रवर्तन एवं निगरानी को और मजबूत किए जाने के निर्देश दिए हैं।

सांप्रदायिक सौहार्द बनाने को पूर्व सैनिकों ने निकाली रैली

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : कुछ दिन पूर्व शहर में दुकान का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद के बाद शहर में शांति व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूर्व सैनिकों ने रैली निकाली। इस दौरान आमजन को सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया गया। कहा कि शहर की शांति व्यवस्था बनी रहें इसके लिए सभी को गंभीरता से कार्य करना चाहिए।

सोमवार को पूर्व सैनिकों ने महेंद्र पाल सिंह रावत के नेतृत्व में मालवीय उद्यान से तहसील तक रैली निकाली। वक्ताओं ने कहा कि कोटद्वार को गढ़वाल का द्वार कहा जाता है।

इसलिए यहां पर शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसके उपरांत प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भी पत्र भेजा गया। जिसमें वन रैंक-वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई गई। कहा कि लगातार शिकायत के बाद भी सरकार समस्या को लेकर लापरवाह बनी हुई है। कहा कि पूर्व सैनिकों को वन रैंक-वन पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति से वन रैंक-वन पेंशन में आ रही विसंगतियों को दूर करवाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित किए जाने की मांग की है। उन्होंने यूजीसी के नियमों में जोड़े गए अधिनियमों पर भी कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि इस प्रकार के अधिनियमों के लागू होने से समाज में खाई पैदा हो जाएगी, जिससे आपसी सौहार्द खराब होने की संभावना है। पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर मेहरबान सिंह, अनसुया प्रसाद सेमवाल, सुषमा भट्ट, देवेंद्र सिंह रावत, गोपाल सिंह, जीत सिंह, ठाकुर सिंह, अनुसूया प्रसाद गोस्वामी, शूरबीर खेतवाल, त्रिलोक सिंह, ओमप्रकाश, प्रकाश रावत मौजूद रहे।

कोटद्वार तहसील में उपजिलाधिकारी संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपते पूर्व सैनिक

इनाम की धनराशि अंकिता व अन्य पीड़ित परिवार को देने की घोषणा

जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार : कोटद्वार में दुकान का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद के बाद झारखंड सरकार के एक मंत्री ने दीपक को दो लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की। ऐसे में दीपक ने यह धनराशि अंकिता के स्वजनों व उत्तराखंड की अन्य पीड़ित बेटियों के परिवार को देने की बात कही। बताते चलें कि 26 जनवरी को दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद के दौरान दीपक कुमार ने स्वयं को नाम मोहम्मद दीपक बताते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इसके बाद से दीपक का यह वीडियो जमकर वायरल हुआ। इसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही कई अन्य बड़े नेताओं ने दीपक की तारीफ की। अब झारखंड सरकार के एक मंत्री ने दीपक को दो लाख रूपए का इनाम देने की घोषणा की है। दीपक ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें इसकी जानकारी मिली है। लेकिन, अगर उन्हें धनराशि दी गई तो वह यह धनराशि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के स्वजनों को सौंप देंगे।

बच्चों को दी पोक्सो अधिनियम की जानकारी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : भाबर क्षेत्र के अंतर्गत इंटर कॉलेज झंडीचौड़ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूली बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को पोक्सो अधिनियम के बारे में भी बताया गया।

बाल कल्याण समिति की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं को किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, बाल अधिकारों व चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 की उपयोगिता की जानकारी दी गयी। कार्यशाला मे निखिल डेविड ने किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सरल भाषा में समझाते हुए बच्चों को उनके अधिकारों एवं संरक्षण के बारे में बताया। प्रज्ञा नैथानी ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भूमिका और आपात परिस्थितियों में इसकी त्वरित सहायता प्रणाली के बारे बताया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश चंद्रा ने पॉक्सो अधिनियम एवं बाल अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को सुरक्षित रहने, सजग रहने और किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।

राजकीय संप्रेषण गृह किशोरी की अधीक्षिका विजयलक्ष्मी ने चाइल्ड हेल्पलाइन और पॉक्सो अधिनियम विषय पर जानकारी दी। जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए समय-समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर प्रधानाचार्य सोहन लाल, सुभाष गुसाईं, विजयलक्ष्मी, पूजा असवाल, धर्मेंद्र सिंह, प्रीति आदि मौजूद रहे।

बूढ़ी काकी का मंचन देख भावुक हुए दर्शक

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : तन्वी संस्था की ओर से मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी बूढ़ी काकी का नाट्य मंचन किय गया। जिसके माध्यम से समाज को बेहतर राह पर चलने का संदेश दिया गया। नाटक का मंचन इस कदर दमदार था कि कई दर्शकों की आंखे गीली हो गई।

कोटद्वार नगर निगम के प्रेक्षागृह में नाटक मंचन का शुभारंभ नगर आयुक्त पीएल शाह ने भगवान नटराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य बेहद समृद्ध है। हिंदी साहित्य में जहां समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार किया गया है, वहीं समाज की तमाम अच्छाईयों को भी पाठकों को सामने लाया गया है। कहा कि युवा पीढ़ी को हिंदी साहित्य से जोड़ने के लिए नाटक सशक्त माध्यम हैं। नाटक में दिखाया गया कि बूढ़ी काकी अपनी पूरी वसीयत अपने भतीजे सुखराम के नाम कर देती है। वसीयत अपने नाम होने के बाद सुखराम व उसकी पत्नी रूपा काकी को भोजन के एक-एक दाने के लिए मोहताज बना देते हैं।

सुखराम के बेटे के विवाह के दौरान जब रूपा बूढ़ी काकी को झूठे पत्तल चाटते देखती है तो उसे अपनी भूल का अहसास होता है और वह बूढ़ी काकी से क्षमा याचना कर उन्हें अपने हाथ से भोजन करवाती है। लेकिन, जैसे ही वह बूढ़ी काकी के मुंह में भोजन का पहला निवाला डालती है, काकी दम तोड़ देती है।

बूढ़ी काकी की भूमि में संस्था की संस्थापक मीनाक्षी शर्मा का अभिनय इस कदर सशक्त रहा कि कई दर्शकों की आंखे नम को गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में जन मौजूद रहा।

टिनशेड स्थायी आवंटन के लिए धरने पर डटे हैं केमसारी के लोग

नई टिहरी। केमसारी टिनशेड आवास का मालिकाना हक देने की मांग को लेकर कॉलोनीवासी 27वें दिन भी धरने पर डटे रहे। शासन–प्रशासन की ओर से अभी तक आंदोलनकारियों की कोई सुध नहीं लिए जाने पर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। पुरानी टिहरी में टिहरी बांध का पानी भरने पर पुनर्वास सुविधा से वंचित करीब 235 शहरवासियों को 2002–03 में बौराड़ी के केमसारी में बनाए गए अस्थायी टिनशेड आवंटित किए गए थे। लेकिन अस्थायी आवंटन अभी तक स्थायी नहीं हो पाया है जिससे लोगों को जर्जर हो चुके टिनशेड में रहना पड़ रहा है। एकता शक्ति संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र खत्री ने बताया कि टिनशेड की बुनियाद और छत सड़ गई है जिससे बारिश का पानी कमरों के अंदर आता है। लोगों का परिवार बढ़ने पर वह एक ही कमरे में रहने को मजबूर हैं। टिनशेड स्थायी आवंटन नहीं होने के कारण वह उसकी मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जिससे सभी कॉलोनीवासी टिनशेड आवास का स्थायी आवंटन की मांग करते आ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस कारण वह आंदोलन करने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है।

नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर झूमें श्रोता

देवभूमि युवा संगठन की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : देवभूमि युवा संगठन की ओर से आयोजित फ्योंली बसंत महोत्सव में लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी की आवाज का जादू देखने को मिला। नेगी व साथी कलाकारों के गीतों ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। देर रात तक लोग नेगी के गीतों का आनंद लेते रहे।संगठन की ओर से मलवीय उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पूर्व विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दे। शाम के समय लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी ने मंच संभाला। सबसे पहले उन्होंने मां दुर्गा की स्तुति की। उन्होंने 'कन प्यारा लगता गौं घर, कन प्यारू कुमों-गढ़वाल...' की प्रस्तुति दी। उनके गीत 'फ्योंली बोलूं कि बुरांश बोलूं...' और 'मै कू इस चुमटि बस...' पर श्रोता मंत्रमुग्ध हो नाचने लगी। 'नमो नारैण बाबा, नमो नारैण...', 'मालू-ग्वीरालू का बीच...', 'गीत लाणा तांदी बल...', 'त्रिजुगी नारेण..' गीतों पर कलाकारों ने भव्य नृत्य प्रस्तुतियां दी। लोकगायक अनिल बिष्ट के गीत 'पाबौ बजारा..' गीत पर श्रोता जमकर नाचे। कार्यक्रम में प्रतीक्षा बमराड़ा ने 'ऐगे चौदिसू मोल्यार, तू भी ऐजा-ऐजा...' और अंजलि खरे ने 'मुल-मुल कैकूं हैंसणी छै तू...' गीतों की प्रस्तुति दी। लोकगायिका श्वेता नेगी ने 'हयूंद का दिन, फिर बौडि ऐगिना..' और लोक गायक मनीष लखेड़ा ने 'सिद्धबली का धाम...', 'ओ भाना रंगीली भाना...' गीतो की प्रस्तुतियां दी। मंच संचालन योगंबर पोली ने किया, जबकि संगीत पक्ष में विनोद चौहान, सुभाष पांडे, सुमित गुसाई, महेंद चंद्र व आशीष नेगी नजर आए। इस मौके पर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष राम कंडवाल, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रमेश भंडारी, जय देव भूमि फाउंडेशन के अध्यक्ष शिवानंद लखेड़ा, देवभूमि युवा संगठन के अध्यक्ष आशीष नौटियाल सहित भारी तादाद में जनसमूह मौजूद रहा।

कोटद्वार के मालवीय उद्यान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या के दौरान प्रस्तुति देते लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी

देश को बचाने के लिए एकजुट होने का संदेश

जयन्त प्रतिनिधि

कोटद्वार : विराट हिंदू सम्मेलन में लोगों ने देश की रक्षा के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। कहा कि देश व समाज हित के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। इस दौरान हिंदू समाज को सचेत करने के लिए अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया।

कुंभीचौड़ में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन का शुभारंभ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया गया। इसके उपरांत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य ऋतुराज ने सभा को संबोधित किया। कहा कि वर्तमान में देश को बाहरी ताकतों से अधिक खतरा देश के भीतर मौजूद जयचंदों से है। कहा कि कुछ ताकतें राष्ट्र व समाज को विभिन्न तरीकों से बांटने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में हिंदू समाज को सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि जब-जब देश में आतंक फैला, संत देश की रक्षा को खड़े नजर आए। यह देश श्रीकृष्ण, श्री राम से लेकर चाणक्य, चंद्रगुप्त, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, शिवाजी महाराज जैसे संतो का है। कहा कि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है, जो सभी को स्वीकार करता है। संघ के बारे में उन्होंने कहा कि संघ चरित्र निर्माण करता है। इससे पूर्व, कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य ऋतुराज, स्वामी हरिदास व ब्रह्म कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय की प्रभारी ज्योति ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जीवा चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। प्राथमिक विद्यालय कुंभीचौड़ की छात्राओं ने गढ़वाली लोकनृत्य, जय भारती पब्लिक स्कूल के छात्रों ने हनुमान चालीस की प्रस्तुति दी। ग्रीन लैंड पब्लिक स्कूल, तल्ला काशीरामपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र-छात्राओं ने भी लोक गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में स्वामी हरिदास ने कहा कि हिंदू सम्मेलन करवाए जाने का मुख्य मकसद हिंदुओं को जागृत करना है। कहा कि देश में सामाजिक समरसता, स्वदेशी, सांस्कृतिक चेतना व राष्ट्रवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ब्रह्म कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय की प्रभारी ज्योति ने कहा कि हमें संस्कारों को संजोए रखने की भी आवश्यकता है। संस्कृति और संस्कार हमारे समाज की आवश्यकता है। इस मौके पर जिला संघ चालक विष्णु अग्रवाल, सिंचाई सलाकार समिति के उपाध्यक्ष ऋषि कंडवाल, मणिराम, लक्ष्मी देवी, प्रदीप गुंसाई, निशा जुयाल, बृजमोहन चौहान, महानंद ध्यानी, प्रकाश डंगवाल, सुनील डोबरियाल, सुनीता कोटनाला, नीतू रावत, सुमन कोटनाला, शैलेन्द्र बिष्ट गढ़वाल, राजेश , जिला प्रचार प्रमुख अरविंद दुदपुडी समेत विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्रायें, महिला मंगलदलों समेत आदि मौजूद रहे।

आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति देते बच्चे

फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए दीपक को जान से मारने की दी धमकी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : बिहार के एक युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फालोअर्स बढ़ाने के लिए दीपक कुमार को जान से मारने की धमकी दी। युवक की पहचान कर पुलिस ने उसे नजदीकी कोतवाली में बुलवाया। मामले में पौड़ी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।मालूम हो कि कुछ दिन पूर्व शहर में दुकान का नाम बदलने को लेकर विवाद हो गया था। जिसके बाद कई लोग सोशल मीडिया पर मामले को लेकर अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक दिन पूर्व ही सोशल मीडिया पर एक युवक ने मामले से संबंधित दीपक कुमार की हत्या करने वाले को दो लाख रुपये देने की बात कही थी। वीडियो वायरल होने के लिए दीपक ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि जांच में मालूम हुआ कि बिहार मोतीहारी निवासी उत्कर्ष नामक व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया से यह पोस्ट की। युवक की पहचान होने के बाद पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया और उक्त व्यक्ति को नजदीकी थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया।

पूछताछ में व्यक्ति ने बताया कि उसके सोशल मीडिया एकाउंड में फालवर्स नहीं बढ़ रहे थे। जिसके बाद उसने दीपक के नाम पर फालवर्स बढ़ाने की सोची। बताया कि कोटद्वार पुलिस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।

स्वानों की कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी से हो रही मौतें

पशु प्रेमियों ने की संक्रमण पर रोक लगाने की मांग

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : भाबर क्षेत्र में पिछले एक माह से निराश्रित स्वानों में कैनाइन डिस्टेंपर की बीमारी लगातार फैलने से स्वान असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। पशु प्रेमियों ने पशुपालन विभाग से संक्रमण को रोकने की मांग की है।

पशु प्रेमी संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रावत, आकृति गौ सेवा संस्था की संचालक सुषमा जखमोला, आकांक्षा रावत, ऋतु डुकलान, हिमांशु शाह, विशाल माने, आशीष अग्रवाल आदि ने बताया कि पिछले एक माह से क्षेत्र में स्वानों में कैनाइन डिस्टेंपर नामक बीमारी फैल रही है। बताया कि स्वानों (कुत्तों) में कैनाइन डिस्टेंपर एक अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा वायरल बीमारी है, जो बुखार, आंखों एवं नाक से मवाद, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी, दस्त और तंत्रिका संबंधी समस्याओं (दौरे) का कारण बनती है। यह हवा या सीधे संपर्क से तेजी से फैलती है, खासकर कम प्रतिरक्षा वाले पिल्लों में। इसका कोई विशिष्ट इलाज नहीं है, इसलिए समय पर टीकाकरण ही बचाव का एकमात्र तरीका है। यह वायरस बहुत घातक है और इसके परिणाम स्वरूप स्थायी तंत्रिका क्षति या मृत्यु हो सकती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। कलालघाटी पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुबोध रंजन ने बताया कि नगर निगम की ओर से भाबर के 14 वार्डों के लिए 200 वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई थी। जबकि भाबर क्षेत्र में स्वानों की संख्या बहुत अधिक है। वैक्सीन कम मिलने से सभी स्वानों पर टीकाकरण नहीं हो पाया जिस कारण बीमारी फैली है। पशुपालन विभाग द्वारा संक्रमण फैलने पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा।

शिविर में गूंजी लो–वोल्टेज की समस्या

उत्तरकाशी। जन–जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रशासन की ओर से न्याय पंचायत ढुइंक में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने गांव में लो–वोल्टेज की शिकायत की। कहा कि लो–वोल्टेज के कारण ग्रामीणों के मोबाइल फोन तक चार्ज नहीं हो पा रहे। नाराज जनप्रतिनिधियों ने ऊर्जा निगम के अवर अभियंता के स्थानांतरण की मांग रखी और इसकी लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई। सोमवार को ढुइंक में जन जन की सरकार शिविर के दौरान उपजिलाधिकारी बड़कोट बृजेश कुमार तिवारी ने जनसमस्याएं सुनीं। शिविर के दौरान 19 शिकायतें दर्ज हुई जिनमें से अधिकांश का मौके पर निस्तारण हुआ। ग्रामीणों ने नौगांव पीएमजीएसवाई की ओर से बनाई जा रही काण्डी डियाड़ी मोटर मार्ग पर सचिन चौहान की ओर से प्रतिकर न दिए जाने की शिकायत दर्ज करवाई।

जिला बदलने के बाद भी दस्तावेजों में टिहरी का ठप्पा

उत्तरकाशी। विकासखंड डुंडा अंतर्गत ग्राम सभा सौंदी की ज्वलंत जनसमस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। ज्ञापन देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा सौंदी अब तक उत्तरकाशी जनपद के मनरेगा पोर्टल से सही रूप से संबद्ध नहीं हो पाया है जिससे ग्रामीणों को रोजगार संबंधी कार्यों में कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों ने अवगत कराया कि ग्राम सभा सौंदी बीते 30 नवम्बर 2023 से जनपद उत्तरकाशी में सम्मिलित है। अब तक तकनीकी एवं अभिलेखी त्रुटियों के कारण शासकीय योजनाओं से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाई है। आधार कार्ड में निवास विवरण संशोधन नहीं हो पा रहा। ग्रामवासियों के आधार कार्ड में अभी भी निवास स्थान टिहरी गढ़वाल प्रदर्शित हो रहा है। समाज कल्याण विभाग को छोड़कर अन्य अधिकांश विभागों से ग्राम सभा सौंदी को योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिससे विकास कार्य बाधित हैं। ग्रामीणों ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक है किंतु अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि ग्राम सभा सौंदी के मतदाता किस विधानसभा क्षेत्र में मतदान करेंगे। सौंदी को गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र जनपद उत्तरकाशी में विधिवत शामिल करने की मांग रखी गई।

स्थानान्तरण पर शिक्षिकाओं को दी गई भावभीनी विदाई

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : विकासखंड कल्जीखाल अंतर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डांगी में लंबी सेवाओं के बाद दो शिक्षिकाओं के अयन्त्र स्थानांतरण होने पर सोमवार को उन्हें भावभीनी विदाई दी है। इसके साथ विद्यालय को 22 साल सेवाएं देनी वाली भोजन माता श्रीमती रेखा देवी को भी विदाई दी गई। विद्यालय बंद होने से उनकी सेवा समाप्त हो गई थी।

ज्ञात हो कि राजकीय जूनियर हाईस्कूल विद्यालय डांगी में विगत 22 वर्षों अपनी सेवाएं दी रही सहायक अध्यापिका श्रीमती मंजू शाह का स्थानांतरण राजकीय जूनियर हाईस्कूल धारी और अंग्रेजी प्रवक्ता श्रीमती सुनीता रावत का स्थानांतरण राजकीय जूनियर हाई स्कूल कुलाड़ हो गया था। प्रभारी प्रधानाचार्य श्रीमती नीलम रावत एवं समस्त शिक्षकों के अथक प्रयासों से सोमवार को दोनों शिक्षिकाओं को भव्य विदाई दी गई।

अंग्रेजी प्रवक्ता श्रीमती सुनीता रावत की नियुक्ति राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डांगी का उच्चीकरण होने पर हुई थी उन्होंने दुर्गम विद्यालय में 16 साल अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सज्जन सिंह नेगी, ग्राम प्रधान थनूल देवेंद्र सिंह रावत, एसएमसी अध्यक्ष एवं पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान डांगी भगवान सिंह चौहान, कलीराम, सुरेन्द्र सिं आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक शैलेश डोभाल ने किया।

शिविर में एडीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं

ग्वीन न्याय पंचायत में आयोजित हुआ शिविर, 33 शिकायतें दर्ज

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के तहत सोमवार को विकासखंड बीरोंखाल की न्याय पंचायत ग्वीन में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 33 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। वहीं 89 पात्र लोगों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित भी किया गया। शिविर में कुल 560 लोगों ने प्रतिभाग किया। शिविर की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल ने की। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनते हुए कई मामलों का समाधान मौके पर किया। शेष शिकायतों के संबंध में उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की इस पहल से क्षेत्रवासियों को एक ही स्थान पर विभागीय सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। साथ ही पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों को कहा कि इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी थलीसैंण कृष्णा त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी सुदर्शन सिंह बुटोला, सहायक अभियंता विद्युत मनोज कुमार, पूर्ति निरीक्षक शशिबाला रावत, एडीओ उद्यान विक्रम सिंह रावत, सहायक अभियंता सिंचाई पवन कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

कारगी में फिर पटरी से उतरी सफाई व्यवस्था, हाईवे किनारे लगे कूड़े के ढेर

देहरादून। नगर निगम के कारगी स्थित मैकेनाइज्ड कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन पर सोमवार सुबह सफाई व्यवस्था पटरी से उतर गई। मशीनें ठप होने के कारण कूड़ा समय से शीशमबाड़ा प्लांट नहीं पहुंच पाया। इस कारण हाईवे के किनारे कूड़े के ढेर लग गए।

इससे पहले भी कई बार कूड़ा ट्रांसपोर्टेशन का कार्य ठप हो चुका है। निगम प्रशासन ने कम्पनी को तत्काल सड़क किनारे डम्प कूड़ा हटाने के निर्देश दिए हैं।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने वर्ष 2023 में विद्या निकेतन इण्टर कॉलेज पदमपुर कोटद्वार से संस्थागत छात्र के रूप में अनुक्रमांक 23056206 से कक्षा-10 की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेरी कक्षा-10 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र व सह अंक पत्र कहीं गुम हो गया है, जो काफी खोजबीन व तलाशने के बाद भी नहीं मिला। मुझे कक्षा-10 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र व सह अंक पत्र की आवश्यकता है। अतः मुझे कक्षा-10 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र व सह अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि निर्गत की जाय।

वंश बिष्ट पुत्र श्री गोकुल सिंह बिष्ट निवासी ग्राम लालपुर, पट्टी सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

(1576/21)

संक्षिप्त समाचार

युवती पर हमला कर मोबाइल लूटने वाला गिरफ्तार

देहरादून। बसंत विहार थाना क्षेत्र में राह चलते महिला के हाथ पर आरी से हमला कर मोबाइल लूटने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि महिला के हाथ पर आरी से हमला नहीं हुआ था। आरोपी के हाथ में लिए गए धातु से बने इंच टेप की खरोंच लगी थी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मूलरूप से बिहार निवासी और हाल जनकपुरी नयागांव में रहने वाली सुमन कुमारी के साथ घटना हुई। बीते छह फरवरी की शाम जब वह शांतिकुंज बसंत विहार जा रही थीं तभी स्कूटर सवार दो युवकों ने उन्हें रोका। आरोप लगाया कि उनके हाथ पर आरी से वार किया और मोबाइल छीनकर भाग गए। केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपी फैजल निवासी प्रिंस चौक को शास्त्रीनगर खाला के पास से दबोच लिया। पूछताछ में फैजल ने बताया कि वह और उसका साथी मनीष उर्फ काली निवासी पटेल नगर नशे के आदी हैं। नशे की लत पूरी करने के लिए उन्होंने यह घटना की। आरोपी से पुलिस ने लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया। फरार उसके साथी की तलाश की जा रही है।

जनपद स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी व प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ

देहरादून। श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज, पथरी बाग में सोमवार को दो दिवसीय जनपद स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. मुकुल कुमार सती, निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड एवं विशिष्ट अतिथि विनोद कुमार ढौंडियाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून ने विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश मोहन डबराल व राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष झलडियाल के साथ संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।

देहरादून से विशाखापत्तनम के लिए 5 दिवसीय प्रेस टूर रवाना

देहरादून। प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो देहरादून सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड के पत्रकारों का 11 सदस्यीय दल विशाखापत्तनम के प्रेस टूर के लिए सोमवार को देहरादून से रवाना हुआ। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं विकास कार्यों को नजदीक से दिखाने के उद्देश्य से पीआईबी देहरादून ने एक प्रेस टूर का आयोजन किया। प्रेस टूर में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के लगभग 11 पत्रकारों को विशाखापत्तनम ले जाया गया है। जहां वे केंद्र सरकार के प्रमुख उपलब्धियों का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे।

यह प्रेस टूर पीआईबी की उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों एवं विकास गतिविधियों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। विशाखापत्तनम में पत्रकार केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों जैसे औद्योगिक विकास, बंदरगाह परियोजनाओं, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं का दौरा करेंगे। प्रेस टूर के कंडक्टिंग ऑफिसर सहायक निदेशक, पीआईबी देहरादून संजीव सुंदरियाल ने कहा कि यह प्रेस टूर उत्तराखंड के पत्रकारों को केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं से जोड़ने का माध्यम है।

इससे न केवल मीडिया को सरकारी उपलब्धियों की गहन जानकारी मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर रखने में भी सहायता मिलेगी।

केंद्रीय बजट 2026–27 आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला: सुबोध उनियाल

देहरादून। भाजपा युवा मोर्चा देहरादून द्वारा श्री गुरू राम राय सभागार, पटेल नगर में आयोजित "युवा बजट सम्मेलन" कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने केंद्रीय बजट 2026–27 को देश के युवाओं को सशक्त बनाने वाला और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति देने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट 2026–27 में युवाओं के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से आने वाले वर्षों में लगभग 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड और मुद्रा जैसी योजनाओं के विस्तार के माध्यम से हजारों नए उद्यम स्थापित होने की संभावना है, जिससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

वनाग्नि की रोकथाम में जनसहभागिता बहुत जरूरी : पोरी

लीसा विदोहन से रोजगार सृजन एवं वनाग्नि सुरक्षा को लेकर जन-जागरूकता सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : वन विभाग के तत्वावधान में लीसा विदोहन से रोजगार सृजन एवं वनाग्नि सुरक्षा जन-जागरूकता के उद्देश्य से एक पौड़ी के रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी की सुमधुर एवं प्रेरणादायक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया।

स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने अपने संबोधन में कहा कि लीसा विदोहन न केवल वन संपदा के संरक्षण का माध्यम है, बल्कि इससे ग्रामीण महिला समूहों को स्वरोजगार के

अवसर प्राप्त होंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों की आजीविका में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम में जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है और इस प्रकार के कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नगर पालिकाध्यक्षा हिमानी नेगी ने कहा कि लीसा विदोहन जैसे कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, जिससे पलायन पर रोक लगेगी।

उन्होंने वनाग्नि सुरक्षा को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए आमजन से वन संरक्षण में सहयोग की अपील की। कार्यक्रम के संयोजक गजेंद्र पाठक ने सीतला खेत मॉडल को उपस्थित जनसमूह के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह मॉडल पर्यावरण संरक्षण, आजीविका संवर्धन एवं सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है। इस अवसर पर डीएफओ सिविल सोयम पवन नेगी, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, व्यापार संघ पौड़ी के अध्यक्ष विनय शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशर सिंह नेगी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

लीसा विदोहन से मिलेगा सतत रोजगार

डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि वन विभाग द्वारा लीसा विदोहन को संगठित, वैज्ञानिक एवं सुरक्षित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने लीसा विदोहन की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि इससे प्राप्त राजस्व का लाभ ग्राम पंचायतों को प्राप्त होता है, जिससे स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि इससे एक ओर वनाग्नि की घटनाओं में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को सतत रोजगार मिलेगा।

वन संरक्षण का दिया संदेश

कार्यक्रम के माध्यम से लीसा विदोहन, वनाग्नि रोकथाम एवं वन संरक्षण को लेकर व्यापक जन-जागरूकता का संदेश दिया गया। विभिन्न नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन सहभागिता और विभागीय समन्वय से वन संरक्षण का प्रभावी संदेश प्रस्तुत किया गया।

अफसर लंबित मामलों का निस्तारित करें

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को सेना, आईटीबीपी व अन्य विभागों के भूमि संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने लंबित मामलों को समन्वय स्थापित कर निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिला सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में सेना, आईटीबीपी एवं अन्य विभागों से संबंधित भूमि मामलों, सीमांकन के समाधान को लेकर चर्चा की। उन्होंने औली में भूमि सीमांकन को लेकर अपर जिलाधिकारी , उपजिलाधिकारी ज्योर्तिमठ, सेना, आईटीबीपी, राजस्व व संबंधित विभागों की टीम गठित कर संयुक्त सर्वेक्षण कर मामलों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को भूमि संबंधी सभी मामलों का निस्तारण शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी व समन्वित तरीके से करने की बात कही। साथ ही उन्होंने शासन स्तर पर लंबित मामलों में अनुस्मारक भेजने को कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी ज्योर्तिमठ चन्द्रशेखर वशिष्ठ, सेना, आईटीबीपी, सहित राजस्व, पर्यटन एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्राथमिक आजीविका गतिविधियों का होगा चयन

स्वयं सहायता समूह सदस्यों का दो दिवसीय क्षमता विकास व बीडीपी प्रशिक्षण शुरू

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : विकासखंड पौड़ी में सोमवार को 55 स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए दो दिवसीय क्षमता विकास एवं बीडीपी (बिजनेस डेवलपमेंट प्लान) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण में महिलाओं को आजीविका गतिविधियों की जानकारी दी गयी। डीपीओ दीपक नेगी ने कहा कि इच्छुक सदस्यों की सूची तैयार की जाएगी और प्राथमिक आजीविका गतिविधियों का चयन किया जाएगा। जिससे वह स्वरोजगार से जुड़ सकें।

प्रशिक्षण के दौरान ब्लॉक मिशन मैनेजर विजय सिंह ने सब्जी उत्पादन, मशरूम, पुष्प उत्पादन, डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई-कढ़ाई, जूट बैग, अगरबत्ती, मसाला प्रसंस्करण सहित विभिन्न संभावित आजीविका गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कैंटीन, कैटरिंग, दुकान एवं मरम्मत सेवाओं जैसे सेवा आधारित उद्यमों के बारे में भी बताया। डीपीओ दीपक नेगी ने महिलाओं को एनआरएलएम, पीएमएफएमई, बैंक ऋण, रिवॉल्विंग फंड, सीआईएफ, सब्सिडी तथा समय पर ऋण के महत्व के बारे में भी जानकारी दी।

उन्होंने प्रतिभागियों को आजीविका संवर्द्धन की अवधारणा, समूह आधारित एवं व्यक्तिगत आजीविका गतिविधियों, सरकारी योजनाओं एवं बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा मार्केट लिंकेज के बारे में भी बताया। इस मौके पर प्रभारी खंड विकास अधिकारी दिनेश नेगी सहित संगीता रावत सहित स्वयं सहायता की महिलाएं उपस्थित रहे।

थल्ली की साधना रावत बनीं आत्मनिर्भर

साधना रावत को ग्रामोत्थान परियोजना से मिली नई पहचान

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली नीति का असर अब गांवों तक साफ दिखायी देने लगा है। जनपद पौड़ी के विकासखंड पौड़ी अंतर्गत ग्राम थल्ली की रहने वाली साधना रावत की कहानी इसका उदाहरण है। ग्रामोत्थान परियोजना और एनआरएलएम से जुड़कर उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की है और अब गांव में एक सफल महिला उद्यमी के रूप में पहचान बना चुकी हैं।

साधना रावत ग्रामोत्थान परियोजना से जुड़ने से पहले सामान्य जीवन जी रही थी। परिवार की आजीविका मजदूरी और खेती पर निर्भर थी। ग्रामोत्थान परियोजना के स्टाफ द्वारा ग्राम पंचायत थल्ली में इन्टरप्राइजेज गतिविधि के अंतर्गत सर्वे किया गया। मानकों के आधार पर साधना रावत का चयन रिटेल शॉप गतिविधि के लिए लाभार्थी के रूप में किया गया। भौतिक सत्यापन के बाद परियोजना के

तहत कुल एक लाख रुपये की गतिविधि लागत में 30 हजार रुपये की सहयोग राशि उपलब्ध करायी गयी। इसके साथ ही सहकारी समिति से 50 हजार रुपये का ब्याज रहित ऋण तथा सीआईएफ से 50 हजार रुपये का ऋण लेकर उन्होंने गांव में रिटेल शॉप शुरू की। पहले साधना रावत केवल कृषि कार्य करती थीं और आय का कोई स्थायी साधन नहीं था। दुकान खुलने के बाद उनकी स्थिति में बड़ा बदलाव आया। साधना की दुकान से प्रतिमाह लगभग 70 से 80 हजार रुपये का व्यवसाय हो रहा है। उनकी दुकान की दैनिक बिक्री 7 से 9 हजार रुपये तक पहुंच चुकी है। बताया गया कि उनका शुद्ध वार्षिक लाभ करीब 80 हजार रुपये है। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। साधना रावत ने कहा कि पहले घर चलाना बहुत मुश्किल होता था और हमें योजनाओं की जानकारी भी नहीं थी। कहा कि ग्रामोत्थान परियोजना और एनआरएलएम से जुड़ने के बाद मुझे सहयोग मिला और आज मैं अपनी दुकान चला पा रही हूं। अब परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं। ग्रामोत्थान परियोजना प्रबंधक कुलदीप बिष्ट ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। साधना रावत की सफलता यह दर्शाती है कि यदि सही मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग मिले तो महिलाएं गांव में रहकर भी अच्छा व्यवसाय खड़ा कर सकती हैं।

डॉ. नित्यानंद का पूरा जीवन–हिमालय, प्रकृति, समाज और राष्ट्र को समर्पित रहा : धामी

सत्तत हिमालयी पर्यावरण पुरस्कार से जयेंद्र राणा और संजय सत्यवली सम्मानित

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दून विश्वविद्यालय, देहरादून में डॉ. नित्यानंद की जन्मशताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सत्तत हिमालयी पर्यावरण पुरस्कार 2025-26 से जयेंद्र सिंह राणा एवं संजय सत्यवली को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने डॉ. नित्यानंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय, प्रकृति, समाज और राष्ट्र को समर्पित किया। उनकी सोच, हिमालय की शिखरों जैसी ऊँची और उनका सेवा-भाव हिमालय की घाटियों से भी गहरा था। उनका मानना था कि

हिमालय की रक्षा करना, भारतीय सभ्यता और राष्ट्र के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. नित्यानंद ने विज्ञान को अध्यात्म से, शोध को लोक-+जीवन से और चिंतन को राष्ट्रहित से जोड़ने का कार्य किया। वो समाज के प्रत्येक वर्ग में राष्ट्रभाव और सामाजिक चेतना का संचार करते रहे। उन्होंने गांवों के सशक्तिकरण के लिए भी आजीवन कार्य किया। वे प्रतिवर्ष अपनी आय से लगभग 40 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली की आपदा के बाद डॉ. नित्यानंद ने बिना किसी विलंब के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया, जो आज भी श्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने मनेरी गांव को अपना केंद्र बनाकर वहां 400 से अधिक भूकंप रोधी मकानों के निर्माण का कार्य भी कराया। उन्होंने उस क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने का कार्य भी किया। इस अवसर पर आर.एस.एस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. दिनेश, आर.एस.एस प्रान्त प्रचारक डॉ. शैलेन्द्र, विधायक विनोद चमोली, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विधायक बृजभूषण गैरोला, डॉ. कमलेश कुमार, उत्तरांचल उत्थान परिषद के संरक्षक प्रेम बड़ाकोटी, कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, रविदेवानंद आदि मौजूद रहे।

ढुंग गांव में आपदा के एक साल बाद भी नहीं बना पुल

उत्तरकाशी। ग्राम पंचायत सिरी के अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव ढुंग में आपदा में बहे पुल का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीण पुल के स्थान पर लकड़ी के फट्टे बिछाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। इसके अलावा गांव की पेयजल लाइनों के साथ नहर क्षतिग्रस्त है लेकिन उनके समाधान के लिए जिला प्रशासन की ओर से अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। डुंडा विकासखंड के सिरी ग्राम पंचायत के ढुंग गांव के शांतिलाल, सुरेंद्र लाल, बैशाखू लाल का कहना है कि 60 परिवार निवास करते हैं। ये लोग गत वर्ष आई आपदा के बाद से भय में हैं। वर्ष 2024 में गांव के समीप से बहने वाली नदी में बाढ़ आने के कारण गांव के पैदल मार्ग सहित पुल आदि क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके साथ ही पाइपलाइन और नहरें भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। गांव को जोड़ने वाला मुख्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। उससे हर दिन ग्रामीण और स्कूली बच्चे आवाजाही करते हैं। जब प्रशासन की ओर से सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद ग्रामीणों ने स्वयं ही वहां पर लकड़ी के फट्टे बिछाकर अस्थायी पुलिया बनाकर आवाजाही शुरू करवाई लेकिन उस पर भी आवाजाही में खतरा बना रहता है।

बजट में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार की प्राथमिकता: भाजयुमो

ऋषिकेश। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से सोमवार को हरिद्वार मार्ग स्थित आईसीए इंस्टीट्यूट में युवा बजट सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए बजट की सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि इस बजट में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मुहैया कराने को प्राथमिकता दी गई है। सम्मेलन का शुभारंभ भाजयुमो प्रदेश मंत्री अजय उनियाल और प्रदेश सह संयोजक कनक धनई ने किया। प्रदेश मंत्री अजय उनियाल ने कहा कि यह बजट युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। प्रदेश सह संयोजक कनक धनई ने कहा कि वर्तमान बजट में युवाओं को देश की विकास यात्रा का केंद्र माना गया है। शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, रोजगार सृजन और डिजिटल नवाचार के लिए किए गए प्रावधान यह दर्शाते हैं कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई तकनीकों, स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रमों में निवेश से युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि वे रोजगार देने वाले भी बनेंगे। यह बजट युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और आकांक्षाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष शिवम टुटेजा ने कहा कि यह बजट देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मज़बूत कदम है। शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और रोज़गार पर केंद्रित प्रावधानों से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और वे राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मौके पर कार्यक्रम संयोजक विवेक शर्मा, ऋषिकेश मंडल अध्यक्ष अनिरुद्ध शर्मा, हर्ष पाल, प्रतीक पाल, अभिषेक रावत, अंकित चौहान, अमन पांडे, जीतेंद्र पाल, खुमेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

जर्जरहाल में चाई गांव स्थित सीता माता मंदिर..

तीन साल से पुजारी के मकान में है माता सीता की मूर्ति

चमोली। चाई गांव में स्थित सीता माता मंदिर जर्जर हालत में पहुंच चुका है लेकिन तीन साल बाद भी न तो इसकी मरम्मत की गई और न ही इसका पुनर्निर्माण किया गया। ऐसे में तीन साल से माता सीता की मूर्ति को पुजारी के मकान के एक कक्ष में रखा गया है। बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों और अधिकारियों ने तीन साल पहले मंदिर का निरीक्षण कर इसकी मरम्मत का खाका भी तैयार किया मगर अभी तक स्थिति नहीं बदली। इससे लोगों में समिति के प्रति आक्रोश पनप रहा है। विकासखंड ज्योतिर्मठ के चाई गांव में सीता माता का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है। मगर यह मंदिर कई वर्षों से जर्जर बना हुआ है। तीन साल पहले जब मंदिर की छत से प्लास्टर झड़ने लगा तो स्थानीय लोगों ने यहां से माता सीता की मूर्ति को मंदिर के पास ही पुजारी के मकान में शिफ्ट कर दिया। उस समय बीकेटीसी ने मंदिर के जल्द मरम्मत की बात कही थी।

मंदिर की हालात जर्जर : उसके बाद कई मौकों पर बीकेटीसी के अधिकारी व पदाधिकारी यहां गए और मंदिर की मरम्मत जल्द शुरू कराने की बात कही लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई प्रगति नहीं हो पाई है। चाई गांव निवासी ईश्वर चौहान, दिलीप सिंह, अखिलेश पंवार, मनोज बिष्ट का कहना है कि मंदिर की हालात जर्जर बनी हुई है।

थत्यूड़ बाजार की अधिकांश सौर ऊर्जा की स्ट्रीट लाइटें पड़ी हैं खराब

नई टिहरी। विकासखंड मुख्यालय का प्रमुख बाजार थत्यूड़ में अधिकांश सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। जिला पंचायत की ओर से बाजार में कुल 10 सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी लेकिन वर्तमान में इनमें से मात्र दो ही लाइटें जल रही है। आठ लंबे समय से बंद पड़ी हुई हैं। थत्यूड़ बाजार में शाम ढलने के बाद पर्याप्त पथ प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण व्यापारियों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पुलिस प्रशासन को भी रात्रिकालीन गश्त के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे के कारण बाजार क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो रहा है।

रोजगार की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया

– जल्द मांग पूरी नहीं होने पर दी 16 फरवरी से बेमियादी धरना शुरू करने की चेतावनी

नई टिहरी। रिंग रोड परियोजना और टीएचडीसी के अधीन कार्यरत कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार न देने विरोध में उत्तरायणी भागीरथी बेरोजगार संघर्ष समिति के बैनर तले बांध प्रभावित और स्थानीय युवाओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जल्द ही मांग पर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर 16 फरवरी से टीएचडीसी कार्यालय और जाख–डोबरा में बेमियादी धरना शुरू करने की चेतावनी दी। उत्तरायणी भागीरथी बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुलदीप पंवार, सचिव मनोज पंवार के नेतृत्व में बांध प्रभावित ग्रामीणों और स्थानीय युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया। समिति के अध्यक्ष पंवार ने कहा कि टीएचडीसी के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगी निटकॉन, शिवालिक, बालाजी सहित अन्य कंपनियां बाहरी राज्यों के लोग को नौकरी पर रख रही हैं। स्थानीय युवाओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। एडीबी की सहायता से जाख–डोबरा क्षेत्र में रिंग रोड का कार्य चल रहा है, वहां भी स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति टिहरी के जिलाध्यक्ष डॉ राकेश भूषण गोदियाल ने कहा कि टिहरी बांध निर्माण के लिए टिहरी के लोगों ने अपनी पैत्रिक भूमि, घर, खेत–खलियान का बलिदान दिया है, लेकिन रोजगार, बिजली और पानी देने के नाम पर यहां के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। बाद में उन्होंने मांग के संबंध में डीएम को ज्ञापन सौंपा। जल्द ही मांग पर कार्रवाई न होने पर 16 फरवरी से आरपार की लड़ाई शुरू करने की चेतावनी दी। इस मौके पर देवेंद्र नौटियाल, शांति प्रसाद भट्ट, विशन सिंह, प्रशांत रावत, रमेश उनियाल, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।

वसंतोत्सव मेले की तैयारियां समय से पूर्ण करें

विभागीय स्टॉल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा

जयन्त प्रतिनिधि।

चमोली : जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को नगर पालिका परिषद गोपेश्वर की ओर से आयोजित होने वाले वसंतोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मेले के दौरान नगर की यातायात, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल व अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिला सभागार में आयोजित बैठक के दौरान नगर के यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए पुलिस उपाधीक्षक को प्लान तैयार करने के

निर्देश दिए। ताकि मेले के दौरान वाहनों की आवाजाही बाधित होने से लोगों को समस्याओं का समाना न करना पड़े। इसके साथ ही मेले के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी को चिकित्सालय में सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंध करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही पेयजल, पार्किंग व अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मेले के दौरान विभागीय स्टॉलों के साथ ही स्थानीय उत्पादों, महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल लगाने की बात कही। ताकि स्थानीय उत्पादों को बढावा देने का कार्य किया जा सके। बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत ने बताया कि मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन के माध्यम से स्थानीय उत्पदों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी निमंत्रण भेजा गया है।

इस माह होने वाले बड़े आयोजनों को लेकर एसपी ने ली अधिकारियों व थाना प्रभारियों की बैठक

चमोली। चमोली जनपद में आगामी दिनों में विधानसभा सत्र, विंटर कार्निवाल और महाशिवरात्रि पर्व जैसे बड़े आयोजन को लेकर चमोली पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने इन आयोजनों को सकुशल, शांतिपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिलास्तरीय अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। एसपी ने महाशिवरात्रि पर्व के दौरान जनपद के प्रमुख शिवालयों व मंदिर परिसरों में होने वाले मेलों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। औली में होने वाले विंटर कॉर्निवाल के लिए सुरक्षा, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था की तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। औली में पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए : औली रोड पर जगह–जगह बर्फ जमी होने से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए कहा गया। जिससे समय पर सड़क को सुचारु किया जा सके। इसी माह भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में प्रस्तावित विधानसभा बजट सत्र के आयोजन को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पुलिस बल के लिए आवासीय व संचार व्यवस्था के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
–सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382–222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com